सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

सफलता की कुंजी

अगर जिंदगी में कुछ पाना हो, तो तरीके बदलो इरादे नहीं

अनमोल विचार

यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाऐं तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो

–चाणक्य

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • EDITOR: ATUL SHARMA • 31 OCTOBER TO 6 NOVEMBER 2019 • VOLUME-12 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • Mobile: 99881-15514 • email:atul_editor@jalandharbreeze.com

ट्रैफिक पुलिस कर रही है आराम और पुलों के नीचे लग रहे है जाम

■ जालंधर से नीरज की विशेष रिपोर्ट

पिछले दिनों पंजाब पुलिस के एक उच्च अधिकारी द्वारा जिलों की पुलिस को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे कि ट्रैफिक पुलिस अधिकारी वाहनों की चैकिंग में समय ना व्यर्थ करते हुये शहरों में बढ़ रही ट्रैफिक समस्या को सुचारू ढंग से चलाने में ध्यान दें परन्तु जिलों की ट्रैफिक पुलिस पर इस आर्डर का कोई असर नहीं है जिसके परिणामस्वरूप पी.ए.पी चौक से लेकर विधीपुर फाटक जो किसी समय अमृतसर बाईपास था जो कि बाद में नैशनल हाईवे का हिस्सा बना दिया गया है। इस पूरे सटैच पर जितने भी व्हीकल अंडरपास बनाये गए है उसका लोगों द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है क्योंकि यह सारा हाईवे घनी आबादी के साथ लगता है और लोगों द्वारा इसका उपयोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए स्लिप रोड पर गलत साईड गाडी चला कर किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप फोकल प्वाइंट अंडरपास वेरका मिलक प्लांट अंडरपास पर रोजाना हैवी व्हीकल कारों मोटरसाईकल वालों द्वारा हाईवे की दोनों तरफ पर बनी स्लिप रोड का प्रयोग करके अंडरपास के नीचे जाम लगा दिया जाता है।

असल में अंडरपास बनाने का मकसद इसलिए होता है किसी भी व्यक्ति ने रोड के दूसरी तरफ या मेन कैरीजेव पर चढ़ना है तो इनके नीचे से यूटर्न लेकर वो अपने सफर को तय करे क्योंकि स्लिप रोड वन वे होती है। इससे भी गंभीर समस्या जो इस हाईवे पर आ रही है जो ट्रैफिक शहर का सोढल अंडरपास से होता हुआ सीधा हाईवे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और ठीक उसी जगह से पी.ए.पी. चौक से आ रहा ट्रैफिक मकसूदां या सोढल अंडरपास की तरफ जाने के लिए उसी हाईवे द्वारा खोला गया एक गलत कट और ट्रैफिक पुलिस आराम कर रही है और बड़े स्तर पर पुलों के नीचे जाम लग रहे है और वातावरण को प्रदूषित किया जा रहा है इस सारे वाक्य से ये लगता है कि ट्रैफिक पुलिस को व्हीकल अंडरपास का मतलब नहीं पता।

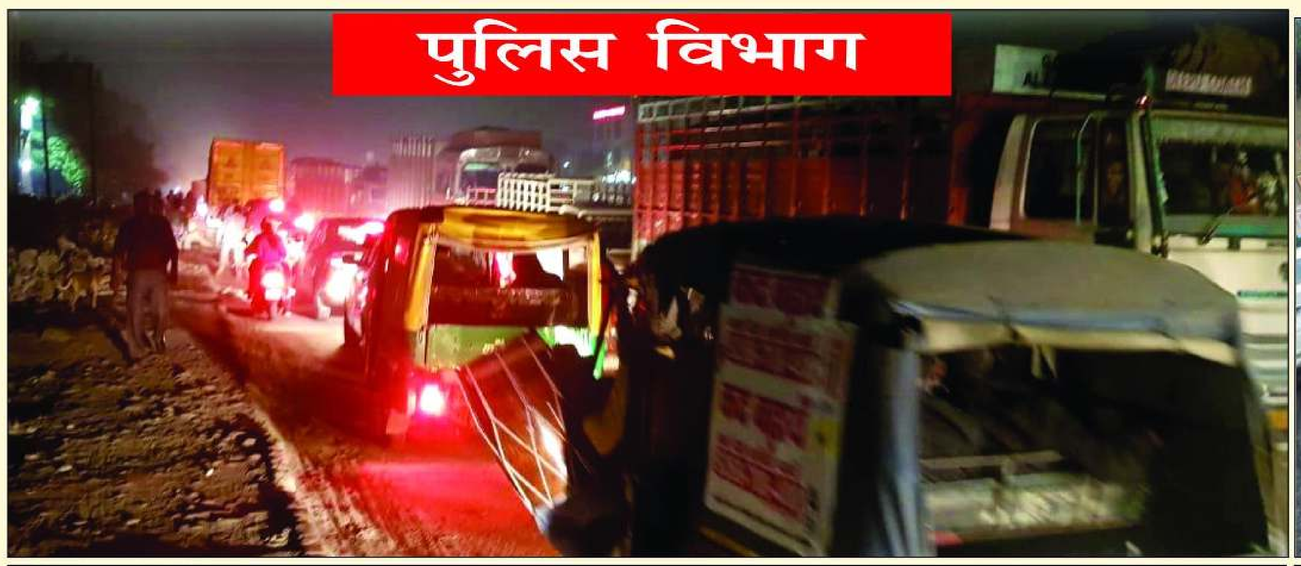

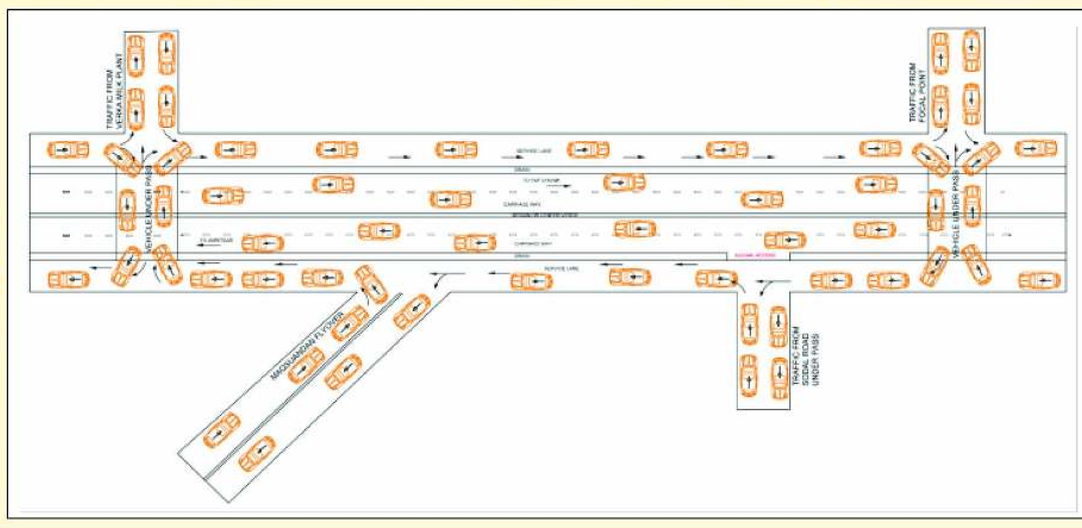

इस नक्शे में साफ-साफ दर्शाया गया है कि व्हीकल अंडरपास में ट्रैफिक इस हिसाब से चलना चाहिए। जबकि हाईवे पर स्थिति इसके विपरीत है।

स्वच्छ भारत मिशन की उड़ रही है धज्जियां

■ जालंधर/ प्रभातसुरी

केन्द्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत योजना के तहत जारी किए गए ग्रांट जिसमें कि खुले में शौच को रोकने के लिए पूरे जालंधर में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर शौचालयों का निर्माण करवाया गया है।

यह निर्माण और इनके रखरखाव का काम नगर-निगम द्वारा एक ही कंपनी को दिया गया है परंतु नगर-निगम जालंधर द्वारा इस के रखरखाव में बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है जिसका एक उदाहरण सोढल रोड़ पर स्थित एक शौचालय जिसके मुख्य द्वार सरकारी संपत्ति पर पान, गुटका, बीडी, सिगरेट बेचा जा रहा है।

ये एक गंभीर मुद्दा है और बड़े स्तर पर केन्द्र सरकार की योजना को नगर-निगम जालंधर द्वारा ठेंगा दिखाया जा रहा है। गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा करने वाला कमिशनर लोगों के पैसे की हो रही बर्बादी के लिए जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करे।

अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत सत्य होने जा रही है

■ जालंधर/ विजय कुमार

गत दिनों यू टयूब पर वायरल हुए वीडियो में डाक्टरों की परस्पर हुई बातचीत से जिसमें एक डाक्टर अपने हस्पताल के अपने हाउस सर्जन को इसलिए डांट डपट कर रहा है कि उसने मरीज को क्यों बताया कि वह स्वस्थ है और उसे एडमिट नहीं किया जा सकता, किस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति को एक डाक्टर सीरियस कंडीशन बताकर दूसरे डाक्टर को रेफेर कर रहा है जब कि वह स्वस्थ है परन्तु पैसे के लालच ने उसे इस कदर जकड़ रखा है कि दूसरा भगवान कहलाने वाले इस डाक्टर को इंसानियत से खिलवाड़ करने वाले इस डाक्टर को इंसानियत ही भूल गयी है क्या इन्हीं डाक्टरों की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार संसद में एक सुरक्षा बिल ला रही है जिसमें इन जैसे इंसानियत से खिलवाड़ करने वाले जो नार्मल डिलीवरी को सिजेरियन बताकर आपेरशन कर डालते है, जो मृत व्यक्ति को वैंटिलेटर पर रख कर आक्सीजन पर रख कर बिल बनाते है जो गैर जरूरी टैस्ट लिख कर और लैब मालिकों द्वारा मरीज को डराकर गलत टैस्ट रिपोर्ट बनवाते है जो फिट व्यक्ति को अनफिट और अनफिट व्यक्ति को फिटनेस सर्टिफिकेट दे देते है और

अनुभवहीन या अनुभव प्राप्त कर रहे डाक्टरों द्वारा सीरियस मरीजों के इलाज करवाते है और उस मरीज के मृत शरीर को तब तक उसके परिजनों को उठाने नहीं दिया जाता जब तक पूरा बिल अदा नहीं हो जाता सिक्योरिटी गार्ड से लेकर बाउंसर तक की सुरक्षा में रहने वाले इन लोगों की मोदी सरकार को बहुत चिंता है जो डाक्टर बनने पर मानवता की सेवा आजीवन करने की शपथ लेते है परन्तु करते उसके विपरीत आचरण फिर भी उसके प्रति सरकार की निष्ठा अथवा विवशता क्यूंकि वे सब लोग जो परस्पर मिल कर गरीब जनता का शोषण करते है और अगर उनके गलत कार्यों पर प्रतिक्रिया करता है तो पहले अस्पताल का स्टाफ उनकी मारपीट करता है फिर भारतीय पुलिस और उस पर कानूनी कार्रवाई 5 से 10 लाख तक की कारवास, यह तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत सत्य होने जा रही है सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता सरकार द्वारा दिए जख्मों को भूलती नहीं सहज भले ही लेती है।

धंधे में जिसका नाम चलता है शर्तें भी वहीं तय करता है न की सरकार!

■ जालंधर से नीरज की विशेष रिपोर्ट

पूरा देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और केंद्रीय सरकार सब को कैश का कम इस्तेमाल करके कार्ड या किसी और डिजिटल माध्यम से पेमेंट करने के लिए प्रेरित कर रही है इसके बदले में बैंकों द्वारा कैश बैक मुहैया भी करवाया जा रहा है।

परन्तु शहर का एक नामी चाईनीज़ रेस्टोरेंट नज़दीक एम.बी.डी मॉल जोकि बढ़िया चाईनीज़ खाना खिलाने के लिए और गाड़ी में बिठा कर शराब पिलाने के लिए मशहूर है इस योजना को ठेंगा दिखा रहा है और उसके द्वारा बीलिंग काऊंटर पर एक तख्ती पर लिखकर रख दिया गया है जिसपर लिखा हुआ है माफ कीजिये हम किसी तरह की पेमेंट क्रेडिट या डेबिट कार्ड से नहीं लेते आपको बिल कैश में चुकाना होगा।

इस रवैये से प्रधानमंत्री का भारत को प्लास्टिक मनी का प्रयोग करने वाला देश बनाने का सपना चकना चूर हो रहा है और जिन लोगों को कैश साथ न रखने की आदत पड़ चुकी है वो इस रेस्टोरेंट में जाने से पहले एटीएम से पैसे निकलवा कर जाएं इस रेस्टोरेंट की एक खासियत और है इसने नोटबंदी के वक्त में भी पूरे 40 दिन हर बिल की पेमेंट कैश में वसूली थी जिससे यह साबित होता है धंधे में जिसका नाम चलता है शर्तें भी वही तय करता है न की सरकार करती है।

दिल्ली पर धुंध का साया

वायु प्रदूषण 'गंभीर' स्तर पर पहुंची

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

दिल्ली पर धुंध का साया लगातार जारी है और बुधवार को भी राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह 11 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 416 था।

सीपीसीबी के अनुसार, मंगलवार को एक्यूआई 414 था, जो सोमवार के एक्यूआई 397 से खराब था। एक्यूआई अगर 0-50 के बीच है तो उसे 'अच्छा' माना जाता है, 51-100 के बीच 'संतोषजनक', 101-200 के बीच 'सामान्य', 201-300 के बीच 'खराब', 301-400 के बीच 'बहुत

खराब' और 401-500 'गंभीर' माना जाता है। अगर एक्यूआई 500 से ऊपर है तो उसे 'गंभीर और आपातकालीन' श्रेणी में माना जाता है। एक्यूआई पांच मुख्य प्रदूषकों को ध्यान में रखता है- 10 माइक्रोमीटर (पीएम10) से कम व्यास वाले पदार्थ, पीएम2.5, ओजोन (ओ3), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ2) और कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ)। एक्यूआई मूल्य जितना अधिक होगा, वायु प्रदूषण का स्तर उतना ही अधिक होगा और स्वास्थ्य की चिंता भी उतनी ही बढ़ जाएगी।

ट्विटर

मुयमंत्री का पद शेयर नहीं किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने पुष्टि की है कि शिवसेना के साथ सीएम पोस्ट को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है।

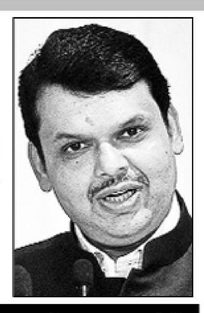

-देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

उक्ति

"जो व्यक्ति जिम्मेदारियों से भागता है, वह अपनी विश्वसनीयता खो देता है। जमाना तो उसी पर भरोसा करता है, जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोताही नहीं बरतता।

- डेविड

दखल

यूपी उपचुनाव नतीजे में छिपे संदेश

उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव परिणाम कई गंभीर निहितार्थों को समेटे हैं। यह परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने के साथ ही सभी दलों के लिए एक कड़ा संदेश भी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस नतीजे से उत्साहित और हतोत्साहित होने वाले सियासी दल अपनी रणनीति में क्या फेरबदल करते हैं?

उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव परिणाम कई गंभीर निहितार्थों को समेटे हैं। यह परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने के साथ ही सभी दलों के लिए एक कड़ा संदेश भी है। इस परिणाम ने रेखांकित किया है कि चाहे सरकार हो अथवा विपक्ष अगर वे जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरते हैं तो जनता उन्हें नजरों से उतारने में देर नहीं करती। मतदाताओं ने साबित किया है कि वे अपने मताधिकार को लेकर जागरूक हैं और अब उन्हें न तो जाति-क्षेत्र की लासेबाजी से गुमराह किया जा सकता है और न ही खोखले वादे से भ्रमित। जनता को सिर्फ विकास चाहिए और अब वह इसे ही पैरामीटर मानकर दलों व उम्मीदवारों का आकलन व मूल्यांकन कर रही है। उपचुनाव के नतीजों पर नजर दौड़ाएं तो इसमें ऐसे ही संकेत छिपे हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी अपना दल के साथ मिलकर आठ सीटें जीतने में कामयाब हुई है। लेकिन उसे एक सीट का नुकसान भी उठाना पड़ा है।

भाजपा को यह नुकसान भले ही छोटा दिखे मगर उसे समझना होगा कि नुकसान के बीज इसी छोटे नुकसान में ही अंकुरित व पल्लवित होते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस नुकसान के कारणों पर गौर नहीं फरमाई और जनता के मिजाज को भांपने में कोताही बरती तो भविष्य में नुकसान के क्षेत्रफल का विस्तार होते देखने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए कि राजनीति में धारणाओं का विशेष महत्व होता है और इस उपचुनाव के नतीजों से साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अजेय नहीं है और उसे पराजित किया जा सकता है। कल तक निराशा के भंवर में डूबी समाजवादी पार्टी ने तीन सीटें जीतकर कुछ इसी तरह का संदेश देने का काम किया है। भले ही उसकी यह छोटी-सी जीत हो लेकिन इस जीत ने उसे ऊर्जा से भर दिया है। कहा भी जाता है कि एक बड़े वृक्ष की संभावना छोटे से बीज में ही निहित होती है। सपा की यह छोटी-सी जीत ही उसके लिए सत्ता तक पहुंचने के मार्ग बन सकती है। इस जीत से सपा गदगद है। इसलिए और भी कि उसकी गिरती साख व कमजोर होती प्रासंगिकता को लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे थे।

लोकसभा चुनाव में बसपा से गठबंधन के बावजूद भी पार्टी को मिली करारी हार पर अखिलेश सवालों के घेरे में थे। लेकिन उपचुनाव में मिली जीत ने उन पर उठने वाले सवालों को थाम लिया है। एकला चलना उनके लिए फायदे में रहा। सपा की इस जीत ने उत्तर प्रदेश में विपक्ष की रिक्तता और शून्यता को लेकर उठ रहे सवालों पर भी विराम लगाया है। अब 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तापक्ष के समक्ष समाजवादी पार्टी ही मुख्य लड़ाई के तौर पर दिखने का प्रयास करेगी। उसकी बढ़ती ताकत से भाजपा से इतर विचारधारा रखने वाले छोटे-छोटे सियासी दल समाजवादी पार्टी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो निःसंदेह जमीन पर समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। और अगर समाजवादी पार्टी मजबूत हुई तो फिर सपा से अलग हुई शिवपाल यादव की प्रसपा का सपा में विलय संभव नहीं होगा। गौर करें तो मौजूदा स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए अनुकूल है। इसलिए कि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में अल्पसंख्यक मतों का जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है। यानी कह सकते हैं कि इस उपचुनाव में विपक्षी दलों में सपा सबसे ज्यादा फायदे में रही। कांग्रेस की बात करें तो इस उपचुनाव में उससे बहुत अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी और हुआ भी वैसा ही। सीटों की हार-जीत के लिहाज से इस बार भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन उसका मत प्रतिशत बढ़कर 12.80 हो गया है। 2017 के चुनाव में उसे 6.25 प्रतिशत मत मिला था।

दो राय नहीं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कई मसलों पर सड़कों पर उतरी और आंदोलन किया और उसका फायदा मत प्रतिशत में इजाफे के तौर पर हुआ है। दूसरी ओर प्रियंका गांधी द्वारा संगठन में आमूलचूल परिवर्तन कर बुजुर्ग नेताओं को किनारे लगाया जाना और बड़े पैमाने पर युवाओं को शामिल किया जाने का असर भी दिखा है। गौर करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ाने वाली पार्टी के तौर पर उभरी है। उसके लिए यह शुभ संकेत है। उसने रेखांकित किया है कि वह प्रदेश से मुक्त नहीं हुई है। लेकिन उसे सत्ता तक पहुंचने के लिए ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना होगा। इस उपचुनाव में सबसे अधिक नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हुआ है। उसका हाथ खाली है। लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने के बाद उसका हौसला सातवें आसमान पर था। उसी जीत से उत्साहित होकर उसने पहली बार उपचुनाव में किस्मत आजमाने का फैसला लिया। लेकिन सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। उसके हिस्से में एक भी सीट नहीं आई। यहां तक कि उसे अपनी एक सीट भी गंवानी पड़ी और आधा दर्जन उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई।

कई स्थानों पर वह कांग्रेस से पीछे चौथे स्थान पर खिसक गई। उसके मत प्रतिशत में भी काफी गिरावट आई है। दरअसल बसपा की रणनीति उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन के जरिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उसकी ओर से 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती का संदेश देना था। साथ ही यह भी साबित करना था कि लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली वह उसकी नीतियों व सिद्धांतों के बदौलत मिली न कि सपा से गठबंधन के कारण। लेकिन उसके सब सपने चकनाचूर हो गए। उसे अपनी ताकत अहसास कराने का मौका तब मिलता जब नतीजे उसके पक्ष में होते। लेकिन नतीजों ने ही उसकी पोल खोल दी है। नतीजों से साफ है कि बसपा की सियासी जमीन सिकुड़ रही है। कोर वोटबैंक यानी दलित समुदाय का अब उससे मोहभंग होने लगा है। गैर-जाटव दलित पहले ही दूरी बना चुके हैं।

अब कह सकते हैं कि गैर-जाटव दलित जातियां भाजपा के साथ हैं। प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा की अधिकांश सुरक्षित सीटें भाजपा ने जीती है। बसपा की हार ने रेखांकित किया है कि उसे 2019 लोकसभा चुनाव में जो 10 सीटें मिली वह सपा से गठबंधन के कारण मिली। अन्यथा उसका हश्र 2014 लोकसभा चुनाव की तरह ही होता। बहरहाल इस स्थिति के लिए खुद मायावती जिम्मेदार है। उन्होंने जिस तरह कांशीराम के समय से जुड़े ताकतवर नेताओं को पार्टी से बाहर कर मनमानी दिखाई और परिवार के लोगों के हाथ पार्टी की कमान सौंपती देखी गई उससे दलित समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं गया है। दलित समाज में धारणा बनी है कि बसपा भी अन्य दलों की तरह परिवारवादी पार्टी बनने की राह पर है। दूसरी ओर जिस तरह बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाकर गठबंधन को तोड़ने का एलान किया उससे भी पार्टी की छवि पर बट्टा लगा है। बसपा सुप्रीमों की छवि एक मौकपरस्त नेता की बनी है।

गौर करें तो 2007 में जब यूपी में बसपा की सरकार बनी तो लगा था कि उसके विजयी रथ को रोकना आसान नहीं होगा। उसकी सोशल इंजीनियरिंग की देश भर में चर्चा रही। लेकिन 2012 के चुनाव में करारी शिकस्त मिली। 2007 के बाद दो विधानसभा और तीन लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और इन सभी चुनावों में बसपा की स्थिति मजबूत होने के बजाए कमजोर हुई है। जनाधार घटा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे मुख्य मुकाबले में आने के लिए अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। बसपा ही नहीं बल्कि अन्य सभी दलों के लिए भी यह उपचुनाव सीख देने वाला है।

■ अरविंद जयतिलक
(वरिष्ठ पत्रकार)

विशेष संपादकीय

महाराष्ट्र में कौन बनेगा सीएम?

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा-शिवसेना के बीच खींचतान के साथ दबाव की राजनीति जारी है। जैसे-जैसे समय बीत रहा है, यह खींचतान कड़वाहट में बदल रही है। महाराष्ट्र का सियासी समीकरण इस समय हर किसी की समझ से बाहर जा चुका है।

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच खींचतान के साथ दबाव की राजनीति जारी है। चुनाव नतीजे के बाद से शिवसेना ढाई-ढाई साल के फार्मूले पर सरकार बनाने पर अड़ी है जबकि भाजपा विधायकों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी होने का हवाला देते हुए इस पर सहमत नहीं है। सोमवार को भाजपा और शिवसेना ने अलग-अलग महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र में सीएम पद पर रस्साकशी के बीच भाजपा-शिवसेना निर्दलीय विधायकों के जरिए अपने समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई हैं। अभी तक छह निर्दलीय विधायक दोनों दलों के समर्थन की बात कह चुके हैं। इनमें से तीन निर्दलीय विधायकों ने भाजपा और तीन ने शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रहार जनशति पार्टी के दो विधायक भी शिवसेना के साथ खड़े हैं। अब दबाव की राजनीति के बीच भाजपा अध्यक्ष अमित शाह 30 अक्तूबर को मुंबई पहुंचने रहे हैं। माना जा रहा है कि वे सरकार के गठन को अमलीजामा पहना सकते हैं। इस विवाद का जो भी नतीजा निकले, मगर अभी तो भाजपा और शिवसेना के बीच जारी बयानबाजी कटुता का रूप ले रही है। मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा और शिवसेना में सियासी कलह चरम पर पहुंच गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने मंगलवार सुबह दुष्यंत चौटाला के सहारे भाजपा पर तंज कसा। राउत ने कहा कि यहां कोई दुष्यंत नहीं है, जिसके पिता जेल में हैं। इसके कुछ देर बाद ही भाजपा ने दो टूक कह दिया कि मुख्यमंत्री का पद शेयर नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि चुनाव से पहले जब गठबंधन को अंतिम रूप दिया गया था तब शिवसेना से ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद का वादा नहीं किया गया था। मैं और पांच साल के लिए मुख्यमंत्री रहूंगा। इस बार भाजपा और शिवसेना दोनों को 2014 की तुलना में कम सीटें मिली हैं। कुछ निर्दलीयों का भी समर्थन मिलने के बाद शिवसेना को लग रहा है कि वह दबाव बनाकर सरकार में टॉप पोस्ट हासिल कर सकती है। खबर है कि बुधवार को महाराष्ट्र भाजपा ने विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी का नेता चुना जाएगा। अपने सहयोगी पर दबाव बनाने के लिए कल ही भाजपा सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकती है। बता दें कि आठ नवंबर तक नई सरकार का गठन होना है। माना जा रहा है कि शिवसेना से बात न बनने पर भाजपा 2014 की तर्ज पर अल्पमत की ही सरकार बना सकती है, जिसके गठन के बाद बहुमत परीक्षण किया जाएगा। भाजपा को उम्मीद है कि पिछली बार की तरह इस बार भी एनसीपी उसे समर्थन दे सकती है। शिवसेना मुख्यमंत्री के पद पर भी दावा कर रही है। हालांकि, ऐसे संकेत हैं कि भाजपा उपमुख्यमंत्री का पद शिवसेना को देने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र की राजनीति पांच दिनों में समुद्र में इतने गहरे तक उतर चुकी है कि यह कह पाना मुश्किल है कि बाहर कौन आएगा।

आतंकी बगदादी का अंत सुखद

अपने उद्भव के बाद कुछ ही समय में समूची दुनिया में खौफ और बर्बरता का पर्याय बन चुके आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईएसआईएस के सरगना अबू-बकर अल- बगदादी के मारे जाने की खबर को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी घटना के रूप में दर्ज किया जाएगा। यों इससे पहले भी कई बार उसके मारे जाने की खबरें आई, लेकिन कुछ समय बाद वे निराधार साबित हुईं। लेकिन अमेरिकी सुरक्षा बल 'डेल्टा कमांडोज' के गोपनीय अभियान के बाद जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं, उनसे तो यही लगता है कि इस बार दुनिया को बगदादी और उसके आतंक से मु ित जरूर मिली है। खबरों के मुताबिक, सीरिया के इदलीब प्रांत के सुदूर गांव बारिशा में एक गुप्त ठिकाने का पता लगाने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने अचानक हमला किया और बगदादी को घेर लिया। कोई विकल्प नहीं देख कर बगदादी ने कमर में बंधे विस्फोटक से खुद को उड़ा लिया। इस मसले पर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की घोषणा की, उससे यही लगता है कि इस बार बगदादी के खात्मे की खबर आखिरी है। इसके बावजूद यह मानना शायद जल्दबाजी होगा कि बगदादी के खात्मे के साथ ही आईएस का समूचा तंत्र ही खत्म हो गया है। गौरतलब है कि बगदादी के मारे जाने की खबरों के बाद यह जानकारी भी सामने आई कि आईएस ने अब अदुल्लाह कार्दश को अपना सरगना चुन लिया। सवाल है कि इसकी या गारंटी है कि अदुल्लाह कार्दश आने वाले व त में बगदादी जैसा ही आतंक नहीं पैदा करेगा! दरअसल, कार्दश ने काफी पहले से आईएस के कई मामलों को संभालना शुरू कर दिया था और सभी आतंकी हमलों को अंजाम देने में कार्दश की मुय भूमिका होती थी। यह छिपी बात नहीं है कि सीरिया और आसपास के देशों तक फैल चुकी लड़ाई में आईएस के खिलाफ अमेरिका, रूस, तुर्की सहित कई देशों के अलग-अलग या फिर संयु त अभियान के बावजूद पिछले कई सालों से इस संगठन ने अपनी मौजूदगी बनाए रखी है। आईएस ने दुनिया का ध्यान पहली बार तब खींचा था, जब उसने इराकी शहर मोसुल पर कजा कर लिया था और यहां तक कि सद्दाम हुसैन के गृह जनपद तिकरित को भी अपने झंडे के नीचे ले लिया था। माना जाता है कि कई देशों की सेनाओं के सामने टिके रहने के पीछे अल-बगदादी की नेतृत्व क्षमता थी। रूढ़िवादी और हिंसक इस्लामी आंदोलन में विश्वास रखने वाले बगदादी ने अपने कजे वाले इलाके में शरीयत के मुताबिक शासन चलाने की घोषणा कर दी थी। इसलिए उसके मारे जाने की खबर निश्चित रूप से आईएस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। यह एक जटिल स्थिति है कि आईएस न केवल मैदानी जंग लड़ने वाला आतंकी संगठन है, बल्कि उसने अपने विचारों के प्रसार और दूसरे देशों के भोले-भाले युवाओं को अपनी चपेट में लेने की भी कोशिश की। यहां तक कि भारत में भी आईएस के एजेंटों ने युवाओं को आकर्षित करने का खूब जाल रचा, लेकिन यहां के सामाजिक और राजनीतिक माहौल की वजह से वह नाकाम रहा। बहरहाल, बगदादी के मारे जाने की खबर ऐसे समय में आई है जब सीरिया में चल रही लंबी लड़ाई के बीच आईएस की जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आने लगी थी, उससे साफ जाहिर था कि लड़ाई के मैदान में उसके पांव उखड़ रहे हैं और वह कमजोर पड़ चुका है। फिर भी इस आतंकवादी संगठन के कामकाज का जो तौर-तरीका रहा है, उसे देखते हुए सीरिया और समूचे इलाके में आईएस के खिलाफ मोर्चा लेने वाले देशों की सेनाओं को उसके समूचे अंत की रणनीति पर काम करना चाहिए। ताकि भविष्य में फिर कोई संगठन आतंक के नाम पर निर्दोष लोगों का खून बहाने की सोच न सके। अब एकबारगी बगदादी के खात्मे पर नजर डालें तो अमेरिकी सेना के स्पेशल कमांडोज ने सीरिया के इदलिब प्रांत के सुदूर गांव बारिशा में शनिवार की रात बगदादी के खिलाफ विशेष ऑपरेशन चलाया। पूरी तरह घिर जाने के बाद बगदादी ने धमाका करके खुद को उड़ा लिया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को औपचारिक रूप से ऐलान किया कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के सरगना अबू बकर अल-बगदादी को मार गिराया गया है। बगदादी के मारे जाने के दावे पहले भी किए जा चुके हैं और रूस को अब भी इस पर यकीन नहीं है। लेकिन जब ट्रंप ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पुष्टि की है तो अविश्वास का कोई कारण नहीं है।

इस तरह बगदादी भी उसी तरह की कार्रवाई में मारा गया जिस तरह ओसामा बिन लादेन मारा गया था। बगदादी लादेन से बहुत ज्यादा प्रभावित था और उसी के न शेकदम पर चलते हुए उसकी मौत का बदला लेना चाहता था। इस तरह दुनिया को दो खूंखार आतंकियों से मु ित मिली जिन्होंने अपने खूनी खेलों से पूरी मानवता को थर्रा दिया था। इस्लामी आतंकवाद का घृणित मुहावरा उनके कारण ही शुरू हुआ। उनके कृत्यों से इस्लाम की उदारवादी छवि कमजोर पड़ी और कई मुल्कों में मुस्लिम समुदाय को संदिग्ध छवि का शिकार होना पड़ा। बगदादी असल में वहाबी विचारधारा से प्रेरित था जिसका उद्देश्य दुनिया में इस्लामी उसूलों पर आधारित मध्यकालीन राज्य की पुनर्स्थापना बताया गया। उसने खुद को खलीफा घोषित किया और सीरिया-इराक के कई इलाकों पर अपना शासन चलाया। बगदादी का मकसद एक मॉडल इस्लामी राज्य कायम करके धीरे-धीरे उसका प्रसार करना था। लेकिन यह उसका सैद्धांतिक पहलू था। व्यवहार में वह पश्चिम एशिया की शिया-सुन्नी राजनीति की पैदाइश था। शियाओं के खिलाफ उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। उसका संगठन इस्लामिक स्टेट शियाओं के खिलाफ गहरी नफरत से भरा था और उसने सभी गैर-सुन्नियों के खिलाफ ाूब खूनी अभियान चलाए। उसकी विचारधारा ने भारत समेत दुनिया के कई चरमपंथियों को प्रभावित किया। उससे असर में कई देशों के नौजवान इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने पहुंच गए। जो संगठन में शामिल नहीं हुए, वे निजी स्तरों पर ही कार्रवाई करने लगे। अनेक देशों में उन्होंने आतंकी गतिविधियां संचालित कीं। अब भी यह कहना मुश्किल है कि बगदादी के मारे जाने से आइसिस की कमर पूरी तरह टूट जाएगी। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि उसके मारे जाने के बाद कोई और उसकी कमान संभाल लेगा, जैसे अभी अदुल्लाह कार्दश को आईएस का मुखिया चुना गया है। आईएस का एक मजबूत नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। एक कड़वी सचाई यह है कि कुछ ताकतवर देशों ने अपने हितों के लिए कई बार ऐसे संगठनों को हथियारों और अन्य तरीकों से सहायता दी है। अगर आतंकवाद को समाप्त करना है तो ऐसी सरकारों से भी सती से पेश आना होगा। लादेन और बगदादी का हश्र बताता है कि हिंसा और अराजकता का अंत एक न एक दिन इसी तरह होना है। आतंकवाद को लेकर आज पूरी दुनिया पीड़ित है, मगर सभी देशों की एक नीति न होने के चलते विश्व को इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। भारत आतंकवाद की समस्या को सभी मंचों पर उठा चुका है, मगर आतंक को पोषित करने वाले कुछ देश समस्या का समाधान होने नहीं दे रहे हैं। अगर आतंक से वाकई छुटकारा पाना है तो सभी देशों को एकजुट होकर कार्रवाई करनी होगी, योंकि आतंक का न तो कोई धर्म होता है और न ही कोई देश। इसके खात्मे से भला सबका होगा।

दिल्ली में दिखेगा नतीजों का असर

हरियाणा से चली सियासी हवा अब राजधानी की सियासत में हलचल पैदा कर सकती है। हरियाणा के चुनावी नतीजे दिल्ली विधानसभा के सियासी मिजाज को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली की तीनों पार्टियां अपने-अपने हक में नतीजे का इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम कर रही है। रणनीतिकार मान रहे हैं कि हरियाणा के साथ महाराष्ट्र के परिणामों से साबित हो गया है कि विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय मसलों पर नहीं लड़ा जाता है। राष्ट्रवाद एवं अनुच्छेद- 370 जैसे मुद्दे विधानसभा चुनाव में ज्यादा असरदार नहीं रहेंगे। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव भी स्थानीय मसलों पर होगा। आप दिल्ली सरकार के बीते पांच साल के कामों को अपनी उपलधि मान रही है। दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस का मानना है कि हरियाणा का चुनाव साबित करता है कि लोग मौजूदा सत्तासीन पार्टी से नाराज है। वह विकल्प की तलाश कर रहे हैं। उनको कांग्रेस के पुराने दिन याद आ रहे हैं। हरियाणा में भाजपा की तरह दिल्ली में आप ने भी दिल्ली वालों से झूठे वादे किए हैं। 2015 विधानसभा चुनाव के बाद के चुनावों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। हरियाणा के नतीजों से न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं में उत्साह आएगा, बल्कि आम मतदाताओं को भी भरोसा कांग्रेस में बढ़ेगा। इसके अलावा भाजपा हरियाणा चुनाव के नतीजों को अपनी जीत मान रही है। इसका सीधा असर हरियाणा से सटे इलाकों पर पड़ने की उम्मीद भाजपा को है। वहीं, कांग्रेस के प्रदर्शन को भी भाजपा अपने हक में मान रही है। भाजपा रणनीतिकारों का मानना है कि इससे उम्मीद है कि दिल्ली कांग्रेस को भी थोड़ी ऊर्जा मिल जाए। ऐसा होने पर दिल्ली का मुकाबला त्रिकोणीय होगा और विपक्षी वोटों के बंटवारे का फायदा भाजपा को मिलेगा। आम आदमी पार्टी (आप) का हरियाणा में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। हरियाणा में आप ने 46 उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आप के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हरियाणा चुनाव से दूरी बनाए रखी थी। कोई भी बड़ा नेता हरियाणा में प्रचार करने नहीं गया था। दिल्ली में 15 साल तक राज करने वाली कांग्रेस अपने पुराने वजूद को वापस पाने की जद्दोजहद से जूझ रही है। अब हरियाणा-महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का असर दिल्ली में दिखाई दे सकता है। हरियाणा चुनाव का असर दिल्ली में ज्यादा है, क्योंकि यह दिल्ली से सटा हुआ राज्य है और जातीय समीकरण से लेकर सामाजिक समीकरण भी हरियाणा और दिल्ली में लगभग एक समान हैं। जिस प्रकार हरियाणा में जाट समुदाय चुनाव में अहम है, ठीक उसी प्रकार दिल्ली में भी हैं। हजारों की संख्या में दिल्ली एवं हरियाणा के लोग एक से दूसरे शहर में रोजाना आते जाते हैं, नौकरी करते हैं, रहन सहन एक है, काम एक है और चुनावी सोच भी मिलती है। इसलिए, हरियाणा के चुनावी मिजाज का असर दिल्ली की राजनीति पर पड़ता रहा है। सो, इस बार भी पड़ना बिल्कुल तय है।

हरियाणा से चली सियासी हवा राजधानी की सियासत में भी हलचल पैदा कर सकती है। हरियाणा चुनाव का असर दिल्ली में ज्यादा है, क्योंकि यह दिल्ली से सटा हुआ राज्य है। जातीय समीकरण से लेकर सामाजिक समीकरण भी हरियाणा और दिल्ली में एक समान हैं।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863,

All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.

25 साल से ज्यादा वक्त से दिल्ली-नोएडा में लोगों को ड्राइविंग सिखा रहे हैं। तरह-तरह के लोग आते हैं, किसी को जल्दी होती है, कोई गुस्सैल होता है, कोई राजनीति बतियाता है तो कोई प्रशासनिक पावर दिखाता है, कुछ लोग अपनी मनमानी करना चाहते हैं, कुल मिलाकर ये समझ लें कि हमारा प्रोफेशन ही सड़क पर और अपने बगल की सीट पर लोगों को झेलना है।

25 सालों से कार चलाना सिखा रहे शख्स ने माना

पुरुषों से बढ़िया गाड़ी चलाती हैं महिलाएं

उत्तरप्रदेश के गाजीपुर में पले-बढ़े हैं हम। अपने वक्त के चलन की तरह कुछ खास पढ़ाई-लिखाई नहीं हुई। जल्दी जवान हो गए, तब बाबूजी के साथ हर काम में हाथ आजमाया। खेती की कोशिश की, मजदूरी की, खाली बैठे, फिर दिल्ली आ गए। तब उम्र थी यही कोई 18 बरस, बड़ी-बड़ी सड़कों पर वैसी ही बड़ी, नए मॉडल की कारें देखते। यह कहना है बाबूनाथ सिंह चौहान का, जो अपने बीते दिनों को याद कर अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं।

उन्होंने बताया कि देखते-देखते कार मैकेनिक बन गए। एक गैरेज में काम शुरू किया, लेकिन ज्यादा वक्त टिक नहीं सके। बाबू लोग आते। कारें कहीं ठुकी होतीं, कहीं घिसी होतीं। हम जतन से गाड़ी सुधारते हैं जैसे अपनी गाड़ी हो, वापसी के वक्त पर कार की चाबी लेते हुए लोग हिकारत से देखा करते हैं। हमारे कपड़े मैले-चीकट दिखते हैं, हाथ-पैर और मुंह पर ग्रीस लगी होती है। कई बार लोग बोलते हैं कि दूर रहो। कई बिना बोले बोल देते हैं। घर लौटते हुए बस में बैठो तो आसपास के लोग उठ जाते हैं या दूर हो जाते हैं, झेंप में हम खड़े-खड़े सफर करने लगे, तब लगा, ये काम तो नहीं हो सकता, तब हमने लाइन ही बदल दी।

25 साल से ज्यादा वक्त से दिल्ली-नोएडा में लोगों को ड्राइविंग सिखा रहे हैं। तरह-तरह के लोग आते हैं, किसी को जल्दी होती है, कोई गुस्सैल होता है, कोई राजनीति बतियाता है तो कोई प्रशासनिक पावर दिखाता है, कुछ लोग अपनी मनमानी करना चाहते हैं, कुल मिलाकर ये समझ लें कि हमारा प्रोफेशन ही सड़क पर और अपने बगल की सीट पर लोगों को झेलना है। भले ही हमारे पास भी ब्रेक, क्लच सब रहता है, लेकिन जान का खतरा तो हरदम बना रहता है, अपनी भी और सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की भी। जितने घंटे काम पर रहते हैं, आंखें और कान दोगुनी तेजी से काम पर लगे रहते हैं।

जीवन में हर चीज नहीं हो पाती पूरी

तकरीबन 50 के होने को आए बाबूनाथ बचपन के सपने के बारे में पूछने पर अकबका जाते हैं। जब छोटे थे तो बहुत कुछ बनने का सोचते थे। थोड़े बड़े हुए तो सोचा कि एसी वाले दफ्तर में काम करेंगे, ये काम करेंगे, वो पाएंगे, लेकिन हर चीज तो हो नहीं पाती है। गैरेज में काम किया तो लोगों की घिन झेली, अब ड्राइविंग सिखाते हैं तो अपने ही स्टूडेंट्स की गालियां भी सुनते हैं, कोई-कोई हड़बड़ी में आता है कि 7 दिन में कार सिखा दो, हम मना कर देते हैं, 7 दिन में कोई कार नहीं सीख लेता, ये झूठ है। तब वो हमें छोड़कर किसी दूसरे ड्राइविंग स्कूल में घुस जाता है, जो यही दावा करता हो।

सहन शक्ति बनाती है महिला को बढ़िया ड्राइवर

औरतें गाड़ी लेकर निकलें तो पढ़े-लिखे लोग भी मजाक उड़ाते हैं। औरत अच्छी ड्राइवर कभी हो ही नहीं सकती, औरतों को दिशा की समझ नहीं, लेफ्ट कहो तो राइट जाएंगी, जान प्यारी हो तो औरत के हाथ में कार की स्टीयरिंग मत दो...ये तमाम बातें सरासर गलत हैं। कम से कम मेरा इतने सालों का अनुभव यही कहता है कि औरतें बहुत बढ़िया ड्राइवर होती हैं। सड़क पर चलने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है, वो उनके पास होती है- सहने की शक्ति, औरतें बिना भड़के चलती हैं, आदमी तो उतावले होते हैं, कहीं का कहीं कर देते हैं। हम सबसे ज्यादा लड़कियों को ही सिखाते हैं। अपनी औरत को भी सिखाया है, कभी-कभी हमको भी उनसे सीखने को मिलता है, हां, ये जरूर है कि पति-पत्नी एक-दूसरे को सिखाएं तो पिकिंग सही नहीं हो पाती। अपने साथी के साथ कोई टीचर जैसे नहीं सीख पाता है।

सरकार को चाहिए कि ट्रेनिंग लेकर आए लोगों को ही दे लाइसेंस

कई लोग इससे भी आगे बढ़कर खुद गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, ये कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा सड़क पर बढ़ते एक्सिडेंट बता देते हैं। थोड़ा सा पैसा बचाने या वक्त बचाने के फेर में अपने साथ रोड पर दूसरों की जान ले लेते हैं। ड्राइविंग स्कूल से सीखने वाले लोग जानते हैं कि कहां चलना है, कैसे मोड़ना है, उन्हें गाड़ी रोकना आता है। सरकार को चाहिए कि ट्रेनिंग लेकर आए लोगों को ही ड्राइविंग लाइसेंस दे। कानून में थोड़ी सी सख्ती कितनी जानें बचा सकेगी। आवाज में मलाल के साथ बाबूनाथ कहते हैं- लोगों को लगता है, कार सीखना एक से दूसरी जगह पहुंचना है। ये इससे कहीं ज्यादा है।

स्पेशल बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा रही हैं शिल्पी

आमतौर पर लोगों की जिंदगी खुद और परिवार तक सिमटी रहती है। वहीं, समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो दूसरों की जिंदगी संवारने की कोशिश में दिन-रात एक कर रहे हैं। लखनऊ के निरालानगर में रहने वाली शिल्पी पाहवा भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। वे स्पेशल बच्चों की प्रतिभा को आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। उनकी संस्था अंदाज-ए-लखनऊ चार साल से अनाथालयों और गरीब परिवारों के बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरा करने में जुटी है।

शिल्पी बताती हैं कि वह साल 2005 में सुप्रयास संस्था से बतौर ट्रेनर जुड़ी। वहां गरीब लड़कियों को मेहंदी और ब्यूटीशियन कोर्स सिखाने लगीं। इससे उनकी सिखाई लड़कियों को रोजगार मिलने लगा। यह देख उन्हें काफी अच्छा लगा। संस्था के साथ काम करते हुए वह चेतना स्पेशल स्कूल में परिवार के सदस्यों का जन्मदिन मनाने जाती थीं।

चार साल पहले अंदाज-ए-लखनऊ की रखी नींव

बकौल शिल्पी, अपने बेटे सार्थक का जन्मदिन मनाते हुए मुझे महसूस हुआ कि बच्चों के साथ केक काट लेने, उन्हें कुछ टॉफी बांट देने भर से वह हमसे नहीं जुड़ेंगे। इसके लिए सार्थक प्रयास करने होंगे। ऐसे में शिल्पी ने चार साल पहले अंदाज-ए-लखनऊ संस्था बनाई। फिर सबसे पहले स्पेशल बच्चों के लिए एक कार्यक्रम करवाया। उन्हें मंच दिया, ताकि वे भी आम लोगों से जुड़ सकें। इसके बाद संस्था ने गरीब, स्पेशल बच्चों और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों की जरूरतें पूरी करने का काम शुरू किया। उनकी संस्था बीच-बीच में बच्चों को साहित्यिक मंच भी मुहैया करवाती है। शिल्पी का कहना है कि इसके जरिए स्पेशल बच्चों के भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है।

पति के सहयोग ने खोला रास्ता

शिल्पी बताती हैं, मुझे हमेशा से लोगों की मदद का शौक था। मेरा यह शौक पति रमन को भी पसंद आया। उन्होंने इसमें हमेशा सहयोग किया। दो बच्चे भी हैं। शुरुआत में संस्था की ओर से हम आर्थिक सहयोग करते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने कभी टोका नहीं। अब तो कई लोग सहयोग कर रहे हैं।

गरीबों को फ्री में खिलाती हैं इडली

चूल्हे पर बनता है खाना

कोयंबटूर में एक रुपए में इडली खिलाने वाली अम्मा की चर्चा के बीच रामेश्वरम की 70 वर्षीय बुजुर्ग अम्मा सामने आईं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में अग्नितीर्थम के पास इडली की दुकान चलाने वाली रानी गरीब लोगों को मुफ्त में इडली खिलाती हैं, जिसके पास पैसे नहीं होते वह उन पर पैसे देने का दबाव नहीं बनाती, अगर पैसे नहीं हैं तो वह फ्री में ही इडली खा सकते हैं। तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक रुपए में इडली खिलाने वाली अम्मा की पिछले दिनों काफी चर्चा रही। इसके बाद अब रामेश्वरम में फ्री में इडली खिलाने वाली 70 वर्षीय बुजुर्ग अम्मा सामने आई हैं। प्रदेश के रामेश्वरम जिले में अग्नितीर्थम के पास इडली की दुकान चलाने वाली रानी गरीब लोगों को मुफ्त में इडली खिलाती हैं।

पैसे देने पर नहीं देतीं जोर

रानी ने बताया कि वह प्रति प्लेट इडली के लिए 30 रुपए लेती हैं, लेकिन ग्राहकों पर इसके लिए जोर नहीं डालतीं। उन्होंने कहा कि जिसके पास पैसे नहीं होते, वह उन पर पैसे देने का दबाव नहीं बनाती हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो वह फ्री में ही इडली खा सकते हैं। रानी की यह व्यवस्था खासतौर पर गरीब तबकों के उन लोगों के लिए है, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते। रानी ने बताया कि वह आज भी चूल्हे पर खाना बनाती हैं और ईंधन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करती हैं।

चूल्हे पर बनाती हैं इडली

बता दें कि इडली तमिलनाडु के लोगों के खान-पान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रानी से पहले कोयंबटूर की इडली वाली अम्मा की भी सोशल मीडिया पर काफी तारीफ की जा रही है। 85 साल की उम्र पार कर चुकीं कमलातल सालों से सांभर और चटनी के साथ एक रुपए में इडली खिलाती आ रही हैं। आसपास के लोग उन्हें एक रुपए की इडली वाली अम्मा के रूप में बुलाते हैं। कमलातल भी लकड़ी के ईंधन से अपना चूल्हा जलाती हैं।

पैसे नहीं तो फ्री में खिलाती हैं इडली

ऐसे में सोशल मीडिया पर फेमस होने के बाद उन्हें कई लोगों की ओर से मदद मिली है। उन्हें फ्री में रसोई गैस कनेक्शन दिया गया है।

बस कंडक्टर की बेटी बनी IPS अफसर

जानिए उनके यहां तक पुहंचने का सफर

बचपन में हर बच्चा बड़े होकर कुछ बनने एवं देश के लिए कुछ करने का सपना देखता है, लेकिन उसे पूरा करने की हिम्मत कुछ लोग ही करते हैं। अपने इसी सपने को पूरा करने की हिम्मत ऊना के ठट्ठल गांव की शालिनी अग्निहोत्री ने की। बचपन में ही उन्होंने बड़े होकर पुलिस में जाकर देश की रक्षा करने का सपना देखा था, जिसे उन्होंने अपनी हिम्मत एवं मेहनत के साथ पूरा किया। पुलिस में भर्ती होने के बाद उन्होंने हिम्मत नही हारी और सर्वश्रेष्ठ आईपीएस ट्रेनी की ट्राफी हासिल की।

पिता है बस कंडक्टर

शालिनी अपने गांव की पहली आईपीएस पुलिस अधिकारी हैं। उनके पिता रमेश एचआरटीसी में बस कंडक्टर है, जिस कारण उनकी ड्यूटी हमेशा लांग रुट वाली बस में लगती थी। इस दौरान वह हफ्ते में मात्र 2 दिन ही घर में रह पाते थे। घर का खर्चा चलाने के लिए शालिनी की मां घर पर सिलाई का काम करती थी। वहीं इनकी बड़ी बहन रजनी डॉक्टर और भाई आशीष इंडियन आर्मी में हैं। आशीष ने पहली बार में एनडीए टेस्ट को क्लीयर कर लिया था।

देर रात 3 बजे तक करती थी पढ़ाई

वहीं शालिनी अपने सपने को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करती थी। वह देर रात 3 बजे तक पढ़ाई करती थी। इतना ही नहीं एमएससी की कक्षाएं लगाने के बाद वह शाम को घर पर अपने टेस्ट की तैयारी करती थी। शालिनी ने धर्मशाला के DAV स्कूल से शिक्षा हासिल कर हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की।

पकड़वा चुकी है अब तक कई अपराधी

बस कंडक्टर की बेटी एवं आईपीएस अधिकारी शालिनी के नाम से अपराधी काफी डरते हैं। जब से उन्होंने कुल्लू में पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाला है, तब से वहां पर अपराधियों में इनका काफी डर रहता हैं। उन्होंने नशे के व्यापारियों के खिलाफी काफी अभियान भी चलाए हैं। इस दौरान उन्होंने दर्जनों अधिकारियों को जेल भी पहुंचाया हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ट्रेनी होने का खिताब अपने नाम किया था। जिसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठित बेटन और गृह मंत्री की रिवॉल्वर दी गई। कुल्लू में अपना कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने मनाली में 40 लाख की लूट, 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के केस को बड़े अच्छे तरीके से संभाला।

अपनी पर्सनालिटी के अनुसार ही चुने हैंड बैग, दिखेंगी परफेक्ट

लड़कियों का बिना पर्स के काम ही नहीं चलता। चाहे उनमें कुछ न होगा पर वो बिना पर्स के बाहर नहीं जाती। बैग्स एक ऐसी अक्सेसरी है जिसकी बिना किसी भी महिला का काम नहीं चल सकता। फैशन के मामले में बैग भी आपकी पर्सनालिटी के अनुसार ही होना चाहिए। यहां कुछ टिप्स हैं, जिनसे आप जान सकती हैं कि आपके लुक और फिजीक को कैसे बैग सूट करेंगे, तो इन तरीकों से जान लें कि आप पर कौनसा हैंडबैग सूट करेगा।

आउटफिट और लुक से करें मैच

हमारे आउटफिट की तरह हमारे बैग्स भी हमारे लुक को प्रभावित करते हैं। महिलाओं के केस में जब हम किसी की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो चाहते हैं कि उन्हें हमारा बेस्ट फीचर दिखाई दे। इसलिए जरूरी है कि ऐसे बैग न लें, जो हमारे आउटफिट और लुक से मैच न करें।

कमर के नीचे शरीर भारी है तो

अगर कमर के नीचे आपका शरीर भारी है तो बेहतर होगा आप शॉर्ट स्ट्रैप वाले छोटे पर्स लें, इस तरह के बैग आसानी से बांह के अंदर आ जाते हैं और लोगों का ध्यान आपके नीचे के शरीर पर नहीं जाता।

दुबले-पतले शरीर वाली

अगर आप दुबले-पतले शरीर की हैं और लंबी हैं तो बैकपैक, क्लच, शोल्डर बैग, मेसेंजर तक सब अच्छा लगेगा। आप ज्यादा छोटे बैग न लें, वरना, आप और लंबी दिखेंगी। मीडियम साइज और बड़े प्रिंट ठीक रहेंगे।

ऊपर का शरीर भारी है तो

अगर आपका ऊपर का शरीर भारी है तो लंबी स्ट्रैप वाले बड़े बैग लें, ताकि ये आपके ऊपरी हिस्से से लोगों का ध्यान हटा दें।

परफेक्ट फिगर

अगर आपकी बॉडी परफेक्ट ऑरग्लास है तो अपने आउटफिट और मौके को ध्यान में रखकर कोई भी बैग ले सकती हैं।

कौन हैं मादी शर्मा, जिन्होंने प्लान किया यूरोपियन यूनियन सांसदों का दौरा, इससे भारत को क्या फायदा होगा

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

मादी शर्मा जिन्होंने यूरोपियन यूनियन के सांसदों का कश्मीर दौरा प्लान किया। मादी शर्मा मादी ग्रुप की हेड हैं। यूरोपीय सांसदों को इन्होंने ही भारत दौरे के लिए आमंत्रित किया था। एक अंग्रेजी वेबसाइट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2019 को मादी शर्मा ने यूरोपीय सांसदों को ईमेल कर 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीआईपी मीटिंग कराने और 29 अक्टूबर को कश्मीर ले जाने का वादा किया था।

यूरोपियन यूनियन के सांसदों के एक दल ने जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा किया। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईयू डेलीगेशन ने कश्मीर में जो देखा, सुना और समझा वह व्यक्त किया। ईयू सांसदों के कश्मीर दौरे को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। विपक्षी दलों की ओर से जहां इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है वहीं इस दौरे के समर्थन में भी कई सारे बयान आ रहे हैं। लेकिन तमाम सवालों, तर्कों और जवाबों के बीच एक नाम जो सुर्खियों में लगातार बना हुआ है वो नाम है मादी शर्मा का। जी हां, वो मादी शर्मा जिन्होंने यूरोपियन यूनियन के सांसदों का कश्मीर दौरा प्लान किया। आइए जानते हैं कौन हैं यूरोपियन यूनियन को कश्मीर दौरे के लिए आमंत्रित करने वाली मादी शर्मा और क्या होगा इस दौरे से फायदा। मादी शर्मा मादी ग्रुप की हेड हैं। यूरोपीय सांसदों को इन्होंने ही भारत दौरे के लिए आमंत्रित किया था। एक अंग्रेजी वेबसाइट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2019 को मादी शर्मा ने यूरोपीय सांसदों को ईमेल कर 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीआईपी मीटिंग कराने और 29 अक्टूबर को कश्मीर ले जाने का वादा किया था। उनके मादी ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है कि यह कई अंतरराष्ट्रीय प्राइवेट सेक्टर और एनजीओ का एक नेटवर्क है। मादी शर्मा एक एनजीओ विमिंज इकॉनमिक ऐंड सोशल थिंक टैंक चलाती हैं। इसके अलावा मादी सोशल कैपिटलिस्ट इंटरनैशनल बिजनस ब्रोकर, एजुकेशनल आंत्रप्रेन्योर ऐंड स्पीकर हैं। बता दें कि यूरोपीय संसद के इन सदस्यों ने अपनी दो दिवसीय कश्मीर यात्रा के पहले, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इनका स्वागत करने के साथ उम्मीद जताई थी कि जम्मू कश्मीर सहित देश के अन्य हिस्सों में उनकी यात्रा सार्थक रहेगी।

ईयू सांसदों के कश्मीर घाटी की यात्रा के महत्व की बात करें तो इस दौरे से कश्मीर के हालातों की वास्तविक और सही तस्वीर दुनिया के सामने लाने की भारत की कोशिश है जो ईयू सांसदों के बयानों के बाद सफल होती दिख रही है। विपक्षी दलों की तरफ से यूरोपीयन डेलीगेशन के कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप जैसी बातें करके इसे पूर्णतः भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला बताया जा रहा है। उनकी बात कुछ हद तक सही है लेकिन इस तरह की कूटनीति से दुनिया भर में पाकिस्तानी दुष्प्रचार को सीधा और खुला जवाब मिलता प्रतीत भी हो रहा है। जब भारत के पास कश्मीर में छिपाने को कुछ नहीं है, हालात धीरे धीरे सामान्? हो रहे हैं, तो फिर यूरोप के सांसदों को या फिर किसी और जगह से आए सांसदों को वहां ले जाने मे क्या बुराई है। और ऐसा करने के बाद परिणाम भी दिखने लगा। जिस तरह से ईयू सांसदों ने पाकिस्तान के खोखले दावों की हवा निकाली और पाकिस्तान को कश्मीर पर दुष्प्रचार करने का दोषी ठहराया। आतंकवाद के मुद्दे और पाकिस्तान के कश्मीर राग पर भी जवाब देते हुए सांसदों ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं, आतंकवाद का मसला यूरोप के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में यूरोपियन सांसदों के इस दौरे से घाटी की सही तस्वीर दुनिया के सामने आई। इस बात में सच्चाई है कि कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। लेकिन ज्ञात हो कि घाटी के हालात पिछले तीन दशकों से खराब हैं। लेकिन अनुच्छेद 370 के हटने के बाद उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। जिसके बाद पूरी दुनिया को इस रोशनी को देखने देने का अवसर देना बेहतर है।

ईडी को नहीं मिली चिंदबरम की कस्टडी, 13 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 13 नवंबर तक के लिये न्यायिक हिरासत में भेज दिया।विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने पूछताछ करने के लिये चिदंबरम को एक दिन की हिरासत में दिये जाने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध को खारिज कर दिया।अदालत ने तिहाड़ अधिकारियों को चिदंबरम को दवाइयां, पश्चिमी शैली का शौचालय, सुरक्षा और अलग कोठरी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर से पका कर लाया हुआ भोजन करने की इजाजत दी जा सकती है। आईएनएक्स मीडिया

मामले में सीबीआई ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और वह धन शोधन के एक मामले में फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मामला चिदंबरम के केंद्रीय वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में विदेशों से 305 करोड़ रुपये की निधि हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितिताओं से संबद्ध है।इसके बाद ईडी ने इस सिलसिले में 2017 में धन शोधन का एक मामला दर्ज किया था। ईडी ने इस साल 16 अक्टूबर को उन्हें हिरासत में लिया था।

बीजेपी नेता का विवादित बयान, मायावती को लेना होगा दूसरा जन्म, सोनिया को राजधर्म का नहीं कोई ज्ञान

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

पत्रकारों से मुखातिब हुए भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए अब दोबारा जन्म लेना होगा। सोनिया गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि सोनिया गांधी को राज धर्म का कोई ज्ञान नहीं है।

अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर सियासी तापमान में इजाफा कर दिया है। इस बार उनके निशाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती औक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी रहीं। मंगलवार को चांदपुर में पत्रकारों से मुखातिब हुए भाजपा विधायक ने कहा है कि मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए अब दोबारा जन्म लेना होगा। सुरेंद्र सिंह ने कहा है, मायावती बीजेपी की वजह से तीन बार मुख्यमंत्री बनीं और बीजेपी का विरोध करना उनके जीवन का तरीका बन गया है। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी ने उन्हें समर्थन नहीं दिया होता तो वह कभी मुख्यमंत्री नहीं बनतीं। मुख्यमंत्री बनने के लिए अब उन्हें दूसरा जन्म लेना होगा। जिसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि सोनिया गांधी को राज धर्म का कोई ज्ञान नहीं है और उन्हें देश की जनता ने पहले ही नकार दिया है। बता दें कि भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह अपने बयानों की वजह से अकसर सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले भी सुरेंद्र सिंह ने एक बयान में कहा था कि मुस्लिम कई पत्नियां रखते हैं और उनके बच्चे जानवर प्रवृत्ति के होते हैं। इतना ही नहीं, वे डॉक्टरों को राक्षस और पत्रकारों को दलाल बोल चुके हैं। हिंदू धर्म बचाने के लिए सुरेंद्र हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील भी की थी। हलांकि, बीजेपी लगातार उनके बयानों को नजरअंदाज करती आई है।

मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं, लेकिन सोनिया जो कहेंगी वह करूंगा- कीर्ति आजाद

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

दिल्ली कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख कीर्ति आजाद ने बुधवार को कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का जो भी आदेश होगा, उसका वह पालन करेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे से जुड़े सवाल पर आजाद ने कहा कि वह फिलहाल सोनिया गांधी की टीम के 'सिपाही' के रूप में कर्म करने में लगे हुए हैं। आजाद ने यह दावा भी किया कि अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

दो दशक के बाद दिल्ली की राजनीति में वापसी करने वाले आजाद ने 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में कहा, ''सोनिया जी ने कहा कि मुझे यह जिम्मेदारी संभालनी है तो मैंने इसे स्वीकार किया क्योंकि मैं खिलाड़ी आदमी हूं, अनुशासन में रहने वाला हूं। आशा करता हूं कि सोनिया जी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है कि उस पर मैं खरा उतरूंगा।'' उन्होंने कहा, '' मैंने 25 साल भाजपा में सेवा की और जब भ्रष्टाचार उजागर किया तो निकाल दिया गया। कांग्रेस में मुझे मान-सम्मान दिया गया है। अपने पिता के घर वापस आया हूं।'' यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस ने उन्हें परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया है तो उन्होंने कहा, ''मैं इन सब चीजों के बारे में सोचता नही हूं। भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख। मैं टीम का सिपाही हूं। मेरी कप्तान सोनिया जो आदेश देंगी, वह मैं करूंगा। मैं आज की सोचता हूं।'' साथ ही उन्होंने यह भी कहा, ''जो कुछ होता है, वह पार्टी तय करती है।'' विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना से जुड़े सवाल पर आजाद ने कहा, '' मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं।'' हालांकि उन्होंने यह भी

कहा, ''राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश होगा, वह मैं करूंगा।'' दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर अपना नाम उछलने के बाद पार्टी के कई नेताओं द्वारा विरोध किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, ''इस विषय पर मैं बात नहीं करता। अगर मुझे कोई पद नहीं मिलता तो भी मैं काम करता।'' उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और सभी नेता साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आजाद ने इस धारणा को भी गलत करार दिया कि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं होने से अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस की चुनौती कमजोर होगी।

यह पूछे जाने पर कि क्या अयोध्या मामले पर अदालती फैसले का असर दिल्ली चुनाव पर होगा तो उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर पड़ेगा।'' आजाद ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर पूर्वांचलियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस वर्ग को हमेशा सम्मान दिया है। उन्होंने दावा किया, ''भाजपा और आप दोनों खुद को पूर्वांचलियों का हितैषी बताते हैं और अगर वे हितैषी हैं तो सिर्फ वोट लेने के लिए हितैषी हैं। पूर्वांचली सम्मान के भूखे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल का लाखों रुपये के इलाज वाला बयान उचित था?

मनोज तिवारी अपने आका को खुश करने के लिए कहते हैं कि अपराध करने वाले 80 फीसदी बाहरी लोग हैं। वह पूर्वांचली होकर भी पूर्वांचलियों का अपमान करते हैं।'' कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि शीला दीक्षित के समय बिजली चोरी पर लगाम लगाए जाने के कारण ही आज केजरीवाल सरकार मुफ्त बिजली से जुड़ा कदम उठा सकी है।

मनप्रीत सिंह बादल ने नई पैंशन स्कीम की पुस्तिका रिलीज़

सभी हिदायतों वाली पुस्तिका जल्द वैबसाईट पर होगी अपलोड

संबंधित पक्षों को मिलेगा लाभ ; मामलों के निपटारे में आएगी तेज़ी

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने आज पंजाब भवन में नई पैंशन स्कीम की एक महत्वपूर्ण पुस्तिका (मैनुअल) रिलीज़ की। इस पुस्तिका में नई पैंशन स्कीम की साल 2018 तक जारी हुई सभी हिदायतों और रैगूलेशनज़ को छापा गया है। इस पुस्तिका के द्वारा नई पैंशन स्कीम के अंशदाता, ड्रॉइंग और डिसबर्सिंग अधिकारी और ज़िला ख़ज़ाना अधिकारियों के अलावा सभी विभागों को एक जगह पर सभी हिदायतें आसानी से मिल सकेंगी जिससे नई पैंशन स्कीम के मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए एक प्रवक्ता ने बताया कि इससे पहले मैनुअल में साल 2018 तक की सभी हिदायतों /रैगूलेशनों को चैप्टर वाइज़ शामिल किया गया है जिसके दो पार्ट और 11 चैप्टर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस पुस्तिका की पीडीएफ फाइल बना कर जल्द ही पंजाब सरकार की वैबसाईट पर अपलोड किया जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुँच हो। गौरतलब है कि मौजूदा समय पंजाब में 1.60 लाख के करीब अधिकारी /कर्मचारी नई पैंशन स्कीम के अंतर्गत नौकरी कर रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा तारीख 1 जनवरी, 2004 और इसके बाद भर्ती हुए अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए नई पैंशन स्कीम लागू की हुई है। इस अवसर पर वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अनिरुद्ध तिवारी के अलावा अन्य सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे।

धर्मसोत द्वारा वन कामगारों की जायज़ माँगें जल्द मानने का भरोसा

राज्य सरकार की नीति के अधीन आने वाले कच्चे कामगारों को पक्का किया जाएगा

अधिकारियों को दैनिक वेतन भोगी कामगारों की सीनियरता सूची 31 दिसंबर तक जारी करने की हिदायत

देहाड़ीदार कामगारों के लम्बित वेतन जल्द जारी करने के आदेश

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के वन मंत्री स. साधु सिंह धर्मसोत ने कहा है कि पंजाब सरकार की नीति के अधीन आने वाले वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कामगारों को पक्का करने की कवायद जल्द शुरू की जायेगी। वन विभाग से सम्बन्धित विभिन्न कर्मचारी जत्थेबंदियों के साथ मीटिंग के दौरान स. धर्मसोत ने विभाग के अधिकारियों को दैनिक वेतन भोगी कामगारों की सीनियरता सूची 31 दिसंबर, 2019 तक जारी करने की हिदायत दी।

उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक समूची जत्थेबंदियों /संबंधितों से ऐतराज़ लेकर सीनियरता सूची को अंतिम रूप दिया जाये। उन्होंने

सीनियरता सूची सम्बन्धी बनाई स्क्रीनिंग कमेटी को कर्मचारी जत्थेबंदियों के साथ नवंबर के पहले हफ्ते एक विशेष मीटिंग करके लम्बित मसले हल के लिए भी कहा। स. धर्मसोत ने कहा कि वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कामगारों की पिछले दो-तीन महीनों के लम्बित वेतन जल्द जारी करने के आदेश देते हुए कहा कि भविष्य में संबंधितों के वेतन हर महीने जारी करने को यकीनी बनाया जाये।

वन मंत्री ने जत्थेबंदियों की अन्य जायज़ माँगों को भी नियमों के अनुसार हल करने का भरोसा दिया। इस अवसर पर डॉ. रौशन सुंकारिया अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, श्री जतिन्दर शर्मा प्रमुख मुख्य वनपाल, श्री हरिन्दर सिंह गरेवाल एम.डी., पंजाब राज्य वन विकास निगम, स. निर्मल जीत सिंह रंधावा, वनपाल और चेयरमैन स्क्रीनिंग कमेटी आदि के अलावा वन विभाग के सीनियर अधिकारी उपस्थित थे।

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

CONSULTING DESIGN TRAINING

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

IELTS • PTE • TOEFL

SPOKEN ENGLISH

TOURIST VISA | STUDY VISA | PR

WORK PERMIT | HOLIDAY PACKAGES

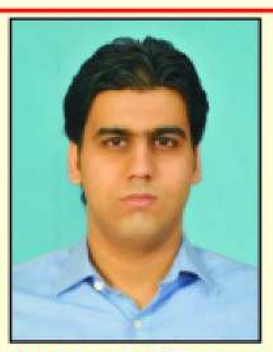

Ankush Sharma

Chartered Engineer

Alumni M.S.(Software Engineering), BITS Pilani

CANADA AUSTRALIA USA U.K SINGAPORE EUROPE

9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal.

HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com

Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin